

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर -1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 13 नवम्बर, 2009

विषय- देहरादून स्थित राजभवन परिसर में श्री राज्यपाल आवास के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0: कैम्प-1/देहरादून दिनांक 01. जून, 2009 के द्वारा देहरादून स्थित राजभवन परिसर में श्री राज्यपाल आवास के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए आगणन लागत रू0 347.84 लाख का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश सं0 828/111(2)/06-49(प्रा0आ0)/2004 दिनांक 28.3.06 के द्वारा देहरादून स्थित श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु रू0 461.00 लाख की प्रशाकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु वर्तमान में मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0 लो0नि0वि0 पौड़ी ने अपने उक्त वर्णित पत्र दिनांक 01 जून, 2009 के द्वारा अवगत कराया है कि महामहिम श्री राज्यपाल के आवास के निर्माण में वास्तुविद् द्वारा दिए गए सुझावानुसार बेसमेन्ट ऐरिया में वृद्धि होने, भवन में ईट चिनाई के बाहरी हिस्से में आर0आर0 पत्थर की चिनाई (टिप सहित) का प्राविधान किए जाने, आर0सी0सी0 छत के ऊपर ट्यूबलर फ्रेम में Galvalume Khaprail Type Sheet के अतिरिक्त कार्य का प्राविधान करने तथा निर्माणाधीन भवन में उच्च विशिष्टियों के अन्य प्राविधान किए जाने के कारण प्रश्नगत कार्य की लागत में वृद्धि हुई है।

चूंकि श्री राज्यपाल आवास के निर्माण में वास्तुविद् के द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार भवन के क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्य की मूल स्वीकृत लागत रू0 461.00 लाख में वृद्धि हुई है अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0 द्वारा उपलब्ध कराए गए देहरादून स्थित राजभवन परिसर में श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु अवशेष कार्यों के आगणन, जिसकी लागत रू0 347.84 लाख, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 326.42 लाख (रू0 तीन करोड़ छब्बीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 787.42 लाख (रू0 सात करोड़ सतासी लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में रू0 326.42 लाख (रू0 तीन करोड़ छब्बीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक: 31 दिसम्बर, 2009 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा सके। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 2- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 के सुसंगत प्रविधानों तथा इसके क्रम में समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कराया जायेगा।
- 3- कार्य पर स्वीकृत नार्म के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि किया जाय।
- 4- यदि उक्त कार्य में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय।
- 5- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण, विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भौति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

Khan

Mishra

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दलों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

8- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

9- स्वीकृत किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में टी0ए0सी0 की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न किया जाय। कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

11- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

12- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही सामग्री का प्रयोग किया जाय।

13- उपर्युक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

14- कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय व्ययक में अनुदान सं0-07 लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य- 800-अन्यभवन -आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं-0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास -24 वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 240/XXVII(2)/2009 दिनांक: 13 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)

अनु सचिव

संख्या- 3645 (1)/111(2)/09-49(प्रा0आ0)/2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद देहरादून।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त आयोग/वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Mitha

(महिमा)

अनु सचिव